वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

सा०/No. : 5-1(17)/2008-PD

दिनांक/Dated: 11.06.2020

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	Government of India,Ministry of Finance, Department of Expenditure OM No. 1/1/2020-E-II dated 23.04.2020.	Freezing of Dearness Allowance and Dearness Relief - reg.

भवदीय/Yours faithfully

11.06.2020

(संतोष कुमार / Santosh Kumar)
अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

3) आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/ Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.

4) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

No. 1/1/2020-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated the 23rd April, 2020.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Freezing of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners at current rates till July 2021.

The undersigned is directed to say that in view of the crisis arising out of COVID-19, it has been decided that the additional installment of Dearness Allowance payable to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners, due from 1st January 2020 shall not be paid. The additional installments of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2020 and 1st January 2021 shall also not be paid. However, Dearness Allowance and Dearness Relief at current rates will continue to be paid.

2. As and when the decision to release the future installment of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2021 is taken by the Government, the rates of Dearness Allowance and Dearness Relief as effective from 1st January 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1st July 2021. No arrears for the period from 1st January 2020 till 30th June 2021 shall be paid.

3 These orders shall be applicable to all Central Government employees and Central Government pensioners.

(Annie George Mathew)
Additional Secretary to the Government of India

To

(i) All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

(ii) Ministry of Railways

(iii) Ministry of Defence

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

फा.सं. 1/1/2020-ई-II (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 23 अप्रैल, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।

2. जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

3. ये आदेश सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
(ii) रेल मंत्रालय
(iii) रक्षा मंत्रालय

प्रतिलिपि: सीएंडएजी, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।